नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 105
दि. 17.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नूंह में अवैध विस्फोटकों का जखीरा बना खतरे की घंटी

(जीएनएस)। हरियाणा के नूंह जिले में अवैध विस्फोटक कारोबार एक बार फिर उजागर हुआ है, जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना बिछौर क्षेत्र के गांव बीसरु में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 900 किलोग्राम प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह बरामदगी एक टीन शैड से की गई, जहां बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के पटाखा निर्माण का काम धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यह साफ हो गया है कि क्षेत्र में अवैध विस्फोटक बनाने और बेचने का संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। जानकारी के अनुसार थाना बिछौर की पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। पुन्हाना–फरदडी मार्ग पर बस अड्डा बीसरु के पास पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि गांव के कुछ लोग अपने खेतों में बारूद से अवैध रूप से पटाखे तैयार कर रहे हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि पीएचसी बीसरु के सामने बीपीएल कॉलोनी में बने एक अस्थायी टीन शैड में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी गई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी।

जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां मौजूद तीन संदिग्ध व्यक्ति खेतों की ओर भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपित अंधेरे और कच्चे रास्तों का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने टीन शैड की तलाशी ली तो वहां 18 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें हल्के पीले रंग का पाउडर भरा हुआ था। जांच में प्रत्येक कट्टे का वजन लगभग 50 किलो पाया गया। विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार यह सामग्री अत्यंत ज्वलनशील और खतरनाक श्रेणी की है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पटाखे या अन्य विस्फोटक उपकरण बनाने में किया जा सकता था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि यह सामग्री किसी वजह से फट जाती तो आसपास की घनी आबादी में भारी तबाही मच सकती थी। बीपीएल कॉलोनी और पीएचसी के नजदीक इतनी बड़ी मात्रा में बारूद का भंडारण करना सीधे तौर पर सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ था।

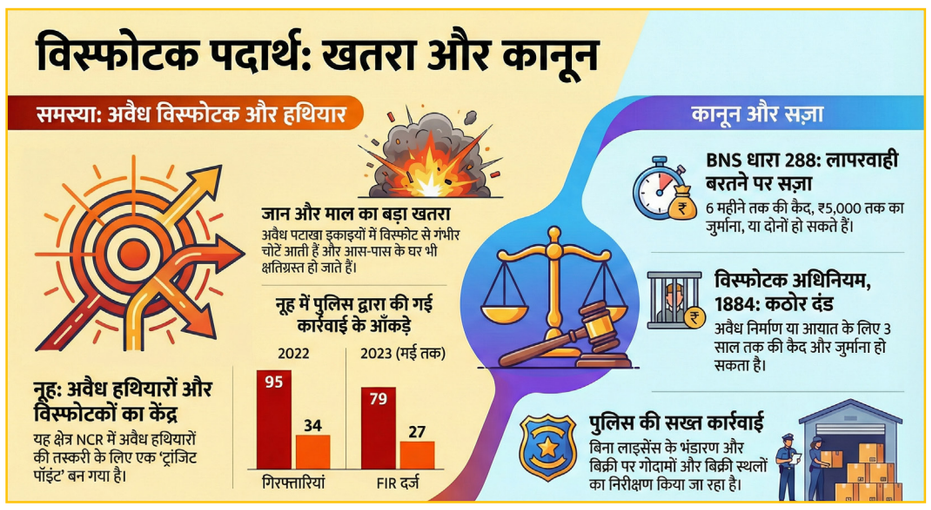

स्थानीय लोगों ने भी स्वीकार किया कि इलाके में लंबे समय से पटाखा बनाने की गतिविधियां चोरी-छिपे चल रही थीं, लेकिन डर और दबाव के कारण कोई खुलकर शिकायत नहीं कर पाता था।

इस मामले में पुलिस ने गांव बीसरु निवासी ईसा, इस्राईल और जुल्ली पुत्र दीनू को मुख्य आरोपित बनाया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का मानना है कि यह केवल तीन लोगों का काम नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे कच्चा माल सप्लाई करने वालों से लेकर तैयार माल बेचने वालों तक की लंबी श्रृंखला काम कर रही है। इसलिए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं।

नूंह जिला पहले भी अवैध विस्फोटकों के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बार छापेमारी के दौरान बारूद, देसी बम और पटाखा बनाने का सामान बरामद हो चुका है। वर्ष 2022 में पुन्हाना और तावडू क्षेत्र में सैकड़ों किलो विस्फोटक पकड़ा गया था। इसके बाद 2023 में सांप्रदायिक तनाव के दौरान चलाए गए अभियान में भी कई संवेदनशील चीजें हाथ लगी थीं। 2024 में फिरोजपुर झिरका के ग्रामीण इलाकों से भी इसी तरह की बरामदगी हुई थी। इसके बावजूद अवैध कारोबार पूरी तरह थम नहीं सका, जो प्रशासनिक तंत्र की चुनौतियों को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध पटाखा निर्माण केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ा है। बेरोजगारी और आसान कमाई के लालच में लोग इस खतरनाक धंधे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी ओर कमजोर निगरानी और सख्त कार्रवाई के अभाव में ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि केवल बरामदगी तक सीमित न रहकर जड़ तक पहुंचा जाए और कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले स्रोतों को बंद किया जाए।

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही स्थायी समाधान की मांग भी की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ा विस्फोट पूरे इलाके को दहला सकता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी कॉलोनियों के पास बारूद का भंडार होना बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे स्थानों की नियमित जांच करे और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उनके मोबाइल नंबरों, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसे कहां खपाने की योजना थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि त्योहारों के मौसम में इस माल को ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी।

यह घटना केवल नूंह जिले की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी है। अवैध विस्फोटकों का फैलता जाल कभी भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। जरूरी है कि समाज, प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर इस चुनौती का सामना करें। जागरूकता, कड़ी निगरानी और त्वरित न्यायिक कार्रवाई ही इस खतरे पर लगाम लगा सकती है, ताकि आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सके।

चाबहार की चुनौती और कूटनीति की कसौटी

(जीएनएस)। ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर उपजी अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बीच भारत ने एक बार फिर स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस रणनीतिक परियोजना से पीछे हटने वाला नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ इस विषय पर निरंतर संवाद जारी है और ऐसे व्यावहारिक विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिनसे भारत के दीर्घकालिक हित सुरक्षित रह सकें। सरकार का मानना है कि चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का वह द्वार है, जो भारत की सामरिक और आर्थिक नीतियों का अहम आधार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को जारी मार्गदर्शक पत्र के तहत कुछ सशर्त ढील दी गई है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 तक है। इसी ढांचे के भीतर भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी तथा कूटनीतिक स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। भारत का प्रयास है कि प्रतिबंधों के जटिल जाल के बावजूद परियोजना की गति बाधित न हो और क्षेत्रीय संपर्क की योजना आगे बढ़ती रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण परिस्थितियां आसान नहीं हैं, लेकिन भारत संतुलित और दूरदर्शी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है।

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए केवल व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भरता कम करने, अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचाने और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह परियोजना वर्षों से भारत की प्राथमिकताओं में शामिल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि चाबहार पर काम रुकता है तो क्षेत्रीय संपर्क की पूरी रणनीति प्रभावित हो सकती है, इसलिए सरकार हर स्तर पर समाधान खोजने में जुटी है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में ईरान में लगभग नौ हजार भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है। इसके अतिरिक्त कुछ नाविक, तीर्थयात्री और कारोबारी भी वहां मौजूद हैं। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारत सरकार समय-समय पर परामर्श जारी कर रही है। नागरिकों से अनावश्यक यात्रा टालने और सतर्क रहने की अपील की गई है। दूतावास के माध्यम से भारतीय समुदाय से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

व्यापारिक मोर्चे पर भारत और ईरान के रिश्तों में आई गिरावट भी चिंता का विषय है। पिछले वित्त वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार घटकर मात्र 1.6 अरब डॉलर रह गया, जिसमें निर्यात 1.2 अरब और आयात केवल 0.4 अरब डॉलर रहा। कभी ऊर्जा और व्यापार के महत्वपूर्ण साझेदार रहे ईरान की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी अब महज 0.15 प्रतिशत रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते भुगतान प्रणाली, बीमा और परिवहन जैसी चुनौतियों ने कारोबार को सीमित कर दिया है। इसके बावजूद भारत ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखने का इच्छुक है।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और चाबहार परियोजना उसी सोच का परिणाम है। भारत एक ओर अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ पारंपरिक मित्रता को भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। यह संतुलन साधना आसान नहीं, लेकिन भारतीय कूटनीति इसी कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। आने वाले महीनों में अमेरिका के साथ वार्ताओं का परिणाम तय करेगा कि चाबहार की राह कितनी सुगम हो पाती है।

फिलहाल इतना तय है कि भारत इस परियोजना को केवल आर्थिक नजरिए से नहीं देख रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय स्थिरता, संपर्क और विकास के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर आगे बढ़ रहा है। बदलती वैश्विक राजनीति के बीच चाबहार भारत की विदेश नीति की परीक्षा भी है और अवसर भी। सरकार के रुख से स्पष्ट है कि तमाम दबावों के बावजूद वह संवाद, संतुलन और दूरदर्शिता के सहारे अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेलवे टेंडर घोटाले में कानूनी जंग तेज, हाईकोर्ट ने सीबीआई को कठघरे में खड़ा किया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब तलब कर राजनीतिक और कानूनी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और पूछा कि किस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपने सभी साक्ष्य और कानूनी दलीलें विस्तृत रूप से पेश करे, ताकि मामले की वैधता पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। यह मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि आईआरसीटीसी के अंतर्गत आने वाले दो होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका देने में नियमों की अनदेखी की गई और इसके बदले कथित तौर पर लाभ हासिल किया गया। सीबीआई का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ। इसी आधार पर एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में तीनों प्रमुख आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए थे। उसी आदेश को चुनौती देते हुए राबड़ी देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप तय किए, वे कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और अभियोजन की अनुमति भी उचित प्रक्रिया से नहीं ली गई। बचाव पक्ष का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।

दूसरी ओर सीबीआई अपने रुख पर अडिग है। एजेंसी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे यह साबित होता है कि टेंडर आवंटन में गंभीर अनियमितताएं हुईं। जांच एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि यह मामला सिर्फ आर्थिक अपराध का नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय भी इस प्रकरण में धन शोधन के पहलुओं की जांच कर चुका है और कई संपत्तियों व लेन-देन को संदिग्ध बताया है।

हाईकोर्ट की इस सुनवाई को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे यह तय होगा कि निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों पर आगे मुकदमा चलेगा या नहीं। यदि अदालत को यह लगता है कि प्रक्रिया में खामियां रही हैं, तो आरोप रद्द भी हो सकते हैं। वहीं, सीबीआई का पक्ष मजबूत पाया गया तो मुकदमे की राह और साफ हो जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यह संदेश भी जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया कितनी सख्ती से काम करती है। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति बता रहा है, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जवाब देना ही होगा। आम जनता की नजरें अब उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सीबीआई को अपना पूरा पक्ष रखना है। यह तय है कि आने वाले दिनों में यह मामला फिर सुर्खियों में रहेगा और इसकी गूंज सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की राजनीति पर भी असर डालेगी।

ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर की जांच पर हाईकोर्ट की ब्रेक, सरकार को सुरक्षा का आदेश

(जीएनएस)। रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए पुलिस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ईडी के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध न तो दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे और न ही जांच संबंधी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस आदेश से केंद्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत मिली है, जबकि राज्य सरकार को ईडी कार्यालय और उसके अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला पेयजल घोटाले के आरोपित संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान कथित दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर को चुनौती देते हुए ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसे जांच एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप तथा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से विस्तृत जवाब तलब किया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसियों के अधिकारियों को उनके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उचित संरक्षण मिलना चाहिए। यदि बिना ठोस आधार के उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो इससे भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच प्रभावित हो सकती है। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ईडी कार्यालय परिसर तथा अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। तब तक पुलिस को इस एफआईआर के आधार पर किसी भी प्रकार की पूछताछ, गिरफ्तारी या जांच संबंधी कदम उठाने से रोक दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेज और तथ्य विस्तृत हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि मामले की वैधानिकता का परीक्षण किया जा सके।

कानूनी जानकारों के अनुसार यह आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थितियां सामने आती रही हैं। उच्च न्यायालय का यह रुख जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे के संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वे अगली सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। ईडी सूत्रों का मानना है कि यह प्रकरण पेयजल घोटाले की चल रही जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से खड़ा किया गया विवाद है। एजेंसी का तर्क है कि आरोपित से पूछताछ पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बहरहाल, हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद गेंद अब न्यायिक पाले में है और सबकी नजर 9 फरवरी की सुनवाई पर टिक गई है, जब इस कानूनी टकराव की दिशा तय होगी।

राजस्थान की मेहमाननवाज़ी से रूबरू होगी राष्ट्रमंडल संसदीय दुनिया

(जीएनएस)। गुलाबी नगर जयपुर एक बार फिर वैश्विक कूटनीति और संसदीय संवाद का साक्षी बनने जा रहा है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राजधानी जयपुर पहुंचेगा। यह यात्रा केवल औपचारिक दौरा नहीं होगी, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक परंपराओं और आधुनिक विकास मॉडल को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में विदेशी अतिथियों के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई हैं। हवाई अड्डे पर मेहमानों का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में अभिनंदन होगा, जहां लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां और शाही रीति-रिवाजों की झलक उन्हें पहले ही क्षण से प्रदेश की आत्मीयता से जोड़ देगी। सरकार और विधानसभा सचिवालय ने इस दौरे को यादगार बनाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है।

देवनानी के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र के अनुभवों का आदान-प्रदान भी है। प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों, किलों, महलों और संग्रहालयों का अवलोकन कराया जाएगा, ताकि वे समझ सकें कि किस प्रकार यह प्रदेश परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। जयपुर, आमेर और आसपास के क्षेत्र भारतीय इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं, जिनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की लंबी यात्रा भी जुड़ी हुई है।

शनिवार सायं कांस्टीट्यूशन क्लब में अतिथियों के सम्मान में भव्य सांस्कृतिक संध्या और रात्रिभोज का आयोजन होगा। इस अवसर पर राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। लोक कलाकार कालबेलिया नृत्य, घूमर, कच्ची घोड़ी और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों से राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति का परिचय कराएंगे। अतिथियों के लिए राजस्थानी व्यंजनों की विशेष थाली भी तैयार की गई है, जिससे वे प्रदेश के स्वाद से भी परिचित हो सकें।

सम्मेलन से लौट रहे इन प्रतिनिधियों के लिए जयपुर प्रवास संवाद का नया मंच बनेगा। विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारी भारतीय संसदीय प्रक्रियाओं, डिजिटल विधान प्रणाली, ई-विधान परियोजना और जनभागीदारी के प्रयोगों को करीब से समझेंगे। राजस्थान विधानसभा द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस अनौपचारिक माहौल में लोकतांत्रिक चुनौतियों, संसदीय आचरण और नागरिक केंद्रित शासन पर खुलकर विचार-विमर्श होगा।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन से राजस्थान की वैश्विक छवि और मजबूत होगी। पर्यटन, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग के नए द्वार खुल सकते हैं। विदेशी प्रतिनिधि जब अपने देशों में लौटेंगे तो साथ ले जाएंगे यहां की मेहमाननवाजी, सुरक्षा व्यवस्था और विकास की सकारात्मक तस्वीर। ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से स्थानीय हस्तशिल्प, होटल उद्योग और सेवा क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलती है।

जयपुर पहले भी कई वैश्विक सम्मेलनों की मेजबानी कर चुका है, लेकिन राष्ट्रमंडल संसदीय नेतृत्व का यह जमावड़ा विशेष महत्व रखता है। लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले भारत के एक ऐतिहासिक राज्य में विश्व के संसदीय प्रमुखों का आना इस बात का संकेत है कि भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल के प्रति दुनिया का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

संपादकीय

विरासत से दयाल सिंह की बेदखली अनुचित

दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने की कोशिशें उन्नीसवीं सदी के एक दूरदर्शी और परोपकारी सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी की स्मृति और विरासत की घोर अवहेलना को ही दर्शाती हैं। यह कॉलेज उन्हीं के नाम पर दिल्ली में स्थापित और प्रतिष्ठित है। 'द ट्रिब्यून' और 'पंजाब नेशनल बैंक' के संस्थापक रहे सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष व समावेशी कॉलेज की स्थापना का स्वप्न साकार करना चाहा, जहां जनहित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली स्थित इस संस्थान का समृद्ध इतिहास 1910 से तब शुरू होता है, जब मजीठिया जी के निधन के बारह वर्ष बाद लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आज कॉलेज प्रबंधन की ओर से दलील दी जा रही है कि एक ही नाम से डे कॉलेज और इवनिंग कॉलेज संचालित नहीं किए जा सकते हैं। यह कहना तार्किक नहीं लगता कि नाम बदलने से प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की सुविधाजनक स्थिति भी बन सकती है। वहीं दूसरी ओर, यह कॉलेज के कलेजे रूपी गरिमामय विरासत और जनभावनाओं को नजरअंदाज करने जैसा है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस बदलाव की कोशिशों के कानून पहलू भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। दरअसल, वर्ष 1978 में हस्तांतरण डीड की धारा 12, जिसके तहत ही दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू ने कॉलेज का अधिग्रहण किया था, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'संस्थान दयाल सिंह कालेज के नाम से ही जाना जाता रहेगा।' इस धारा का उल्लंघन करने की स्थिति में भूमि अधिकार छीनने और जबरन विस्थापन जैसी गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह का जोखिम कोई भी जिम्मेदार प्रशासन हल्के में नहीं लेना चाहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संकाय सदस्यों को सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव की जानकारी तब मिली जब पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने वीर बाल दिवस के मौके पर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी।

यहां उल्लेखनीय है कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज एक कालखंड की गरिमामय स्मृतियों को सहेजे हुए है। भारत मां के महान सपूत सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने अपने सारी संपत्ति समाज के लिये समर्पित कर दी थी। उन्होंने अपना जीवन एक स्वतंत्र प्रेस, उत्तर भारत में शिक्षा के प्रसार के लिये एक उच्चस्तरीय कॉलेज तथा जागरूकता के लिये पुस्तकालय की स्थापना के लिये लगाया। जिसका मकसद समाज में प्रगतिशील सोच विकसित करना और अज्ञानता को समाप्त करना ही था। ऐसे में एक पुनीत उद्देश्य के लिये स्थापित कॉलेज का नाम बदलने का प्रबंधनतंत्र द्वारा इस तरह का एकतरफा निर्णय विश्वविद्यालय के मूल सिद्धांत को ही कमजोर करता है। जिसका मूल उद्देश्य परामर्श और आम सहमति से कार्य करना होता है। इन कोशिशों के बीच कॉलेज के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने ऐसे किसी प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है। कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव में कॉलेज की पहचान और भविष्य को प्रभावित करने वाले इस कदम को लेकर असंतोष जताया गया है। छात्रों में भी इस बात को लेकर रोष देखा गया है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं होता, बल्कि सामूहिक स्मृति का संरक्षक भी होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भी महाविद्यालय का नाम बदलकर 'वंदे मातरम् महाविद्यालय ' रखने का प्रयास किया गया था। लेकिन यह प्रयास हितधारकों के विरोध के चलते सिरे नहीं चढ़ सका था। अब बदलाव की कोशिश करने वालों को पिछले असफल प्रयास को एक सबक के रूप में देखना चाहिए था। दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसे किसी प्रयास से पहले विचार विमर्श करने तथा चिंतन करने की आवश्यकता है। खासकर, ऐसे वक्त में जब एक महान व्यक्तित्व का नाम और साथ ही एक सदी से अधिक की शैक्षणिक और नैतिक विरासत दांव पर लगी हो।

शिक्षक के सम्मान को महत्व देती नई शिक्षा नीति

> नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अधिकतर चर्चाएं पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न पर होती हैं, लेकिन इस महायोजना के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षक है। यह नीति स्वीकार करती है कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे लागू करने वाला शिक्षक सशक्त, संतुष्ट और सम्मानित महसूस न करे।

शिक्षा किसी भी जीवंत राष्ट्र की वह नींव होती है जिस पर उसकी प्रगति का भव्य महल खड़ा होता है। भारत ने वर्ष 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये इसी नींव को आधुनिक, लचीला और वैश्विक बनाने का संकल्प लिया है। अक्सर चर्चाएं केवल छात्रों के पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न पर सिमटकर रह जाती हैं, लेकिन इस महायोजना के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ शिक्षक है। यह नीति इस सत्य को स्वीकार करती है कि कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे लागू करने वाला शिक्षक सशक्त, संतुष्ट और सम्मानित महसूस न करे।

पुरानी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी शिकायत यह रही कि शिक्षक प्रशासनिक कार्यों और जटिल डेटा एंट्री के बोझ तले दबे रहते थे। एनईपी 2020 इस व्यवस्थागत जड़ता को तोड़ने का वादा करती है। नीति में स्पष्टतया 'रोडमैप' तैयार किया गया है जो शिक्षकों को उन गैर-शैक्षणिक गतिविधियों से मुक्ति दिलाने की बात करता है जो उनके मूल धर्म –पढ़ाने- में बाधा डालते हैं। नीति का मानना है कि शिक्षक की ऊर्जा का निवेश केवल फाइलों में नहीं, बल्कि छात्रों के मस्तिष्क में कौतूहल पैदा करने में होना चाहिए। यह बदलाव शिक्षकों को वह रचनात्मक आजादी देगा, जिसकी वे दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे कक्षा में सिर्फ एक तय पुस्तक तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मौलिक नए प्रयोग करेंगे।

एक उत्कृष्ट शिक्षक वह है जो हमेशा एक जिज्ञासु 'विद्यार्थी' बना रहता है। नई नीति ने इस विचार को 'नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स' के माध्यम से संस्थागत रूप दिया है। पहली बार भारतीय शिक्षकों के कार्यों का एक ऐसा पैमाना

तय किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बराबरी करेगा। इससे हमारे शिक्षकों को वैश्विक पहचान मिलेगी। इसके समानांतर, सतत व्यावसायिक विकास के जरिये प्रत्येक शिक्षक को अपनी रुचि अनुसार साल में न्यूनतम 50 घंटे आधुनिक प्रशिक्षण का हक दिया गया है। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समावेशी शिक्षा जैसे विषयों में पारंगत करने का मंच होगा। जब शिक्षक का ज्ञान आधुनिक होगा, तो कक्षा में उनका आत्मविश्वास और प्रभाव स्वतः बढ़ जाएगा। एनईपी 2020 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार की वकालत करती है। अब शिक्षक भर्ती केवल अंकों की दौड़ तक सीमित नहीं होगी। इसमें साक्षात्कार और कक्षा में पढ़ाने के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को शामिल किया जाना इस पेशे की गंभीरता दर्शाता है। इसका बड़ा लाभ यह कि भविष्य में आपके सहकर्मी वे लोग होंगे जो असल में 'शिक्षण के प्रति जुनूनी' हैं। जब स्टाफरूम में समान विचारधारा वाले और योग्य सहकर्मी होंगे, तो कार्यस्थल संस्कृति में क्रांतिकारी सुधार आएगा। यह नीति सुनिश्चित करती है कि शिक्षण का पेशा सबसे मेधावी युवाओं की प्राथमिकता बने। योग्य सहकर्मी आने से कार्यभार साझा होगा और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल बनेगा।

भारतीय संस्कृति में अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एनईपी 2020 इसी परंपरा को 'नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग' के माध्यम से पुनर्जीवित कर रही है। यह ऐसा अनूठा सेतु है जो सेवानिवृत्त और अनुभवी शिक्षकों को नए शिक्षकों के साथ जोड़ता है। अक्सर सेवा के बाद शिक्षकों का विशाल अनुभव व्यर्थ चला जाता था, लेकिन अब उन्हें समाज के 'बौद्धिक संरक्षक' के रूप में नई भूमिका मिलेगी। वरिष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन नए शिक्षकों के लिए सुरक्षा कवच जैसा होगा, जो उन्हें कैरियर की शुरुआती चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।

शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर नयी नीति ने 'मेरिट-आधारित' तंत्र का प्रस्ताव दिया है। अब पदोन्नति का रास्ता केवल वर्षों की सेवा से होकर नहीं गुजरेगा, बल्कि शिक्षक के शोध, नवाचार और छात्रों की प्रगति से तय होगा। यह उन शिक्षकों के लिए स्वर्णिम अवसर है जो अपनी शिक्षण पद्धति बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। साथ ही, उच्च शिक्षा में शिक्षकों को लचीली कार्यसंस्कृति मिलेगी। यदि कोई शिक्षक अनुसंधान में उत्कृष्ट है, तो वह उस दिशा में बढ़ सकता है, और यदि किसी का झुकाव अध्यापन की ओर है, तो वह उसमें विशेषज्ञता हासिल करे।

अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वह दर्जा नहीं मिलता था जो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को मिलता था। एनईपी 2020 ने इस भाषाई भेदभाव को खत्म कर दिया। नीति ने मातृभाषा में शिक्षण को प्राथमिकता देकर उन शिक्षकों का सम्मान बढ़ाया है जो अपनी मिट्टी की भाषा में ज्ञान देने में माहिर हैं। इसके साथ ही, टेक्नोलॉजी को शिक्षक के 'सहयोगी' के रूप में पेश किया गया है। 'दीक्षा' और 'स्वयं' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों को वह कंटेंट और टूल्स दे रहे हैं जिन्हें तैयार करने में पहले घंटों लगते थे। टेक्नोलॉजी उन्हें प्रशासनिक कार्यों से बचाकर वह समय देगी जिसमें वे छात्रों के 'मेंटोर' बन सकें।

नयी शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षक को केवल निर्देशों का पालन करने वाला कर्मचारी नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं। '360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड' की शुरुआत इसी विश्वास का प्रमाण है। अब छात्र के भविष्य का फैसला केवल मशीन से जांची गई शीट नहीं करेगी, बल्कि शिक्षक का वह सूक्ष्म अवलोकन करेगा जिसने बच्चे के मूल्यों और कौशल को करीब से देखा है। जब समाज शिक्षक की राय पर इतना भरोसा जताता है, तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है। भारत के 'विश्व-गुरु' बनने की यात्रा तभी संभव है जब समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को भी अवसर दे रही है कि वे अपनी विशेषज्ञता दुनिया के सामने रखें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो आत्मनिर्भर और संस्कारवान हो।

प्रेरणा

नवोन्मेष का दीपक और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक या राष्ट्रपति भर नहीं थे, वे भारत के भविष्य के स्वप्नद्रष्टा थे। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक तरक्की सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि सामान्य नागरिकों की सोच और परिश्रम से जन्म लेती है। वे अक्सर कहा करते थे कि विकसित देश बनने के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचानना होगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका स्वयं तय करनी होगी। उनके लिए विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें या तेज़ रफ्तार गाड़ियां नहीं था, बल्कि ऐसा समाज था जहां विज्ञान, प्रकृति और मानवता एक साथ आगे बढ़ें।

डॉ. कलाम मानते थे कि भारत के पास अपार संसाधन हैं, परंतु उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता है। वे युवाओं और विद्वानों से लगातार संवाद करते रहते थे और उन्हें नए विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना था कि यदि एक भी नया विचार धरातल पर उतर जाए तो वह हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। इसी सोच के साथ वे स्वयं भी ऐसे उपाय खोजते रहते थे जो देश को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकें।

एक बार उन्होंने रोजगार सृजन और ऊर्जा संकट के समाधान को जोड़ते हुए जट्रोफा के पौधों का सुझाव दिया। जब उन्होंने यह विचार रखा कि देश में बड़े पैमाने पर जट्रोफा के पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो कई लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह विचार सामान्य योजनाओं से बिल्कुल अलग था। परंतु कलाम साहब ने बड़े सरल ढंग से समझाया कि जट्रोफा ऐसा पौधा है जो बंजर और अनुपजाऊ जमीन पर भी आसानी से उग सकता है। उसे न अधिक पानी चाहिए और न महंगी खाद। एक बार लग जाने पर यह लगभग पचास वर्षों तक फल देता रहता है। इसके बीजों से निकला तेल डीजल में मिलाकर जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह केवल एक पौधा लगाने की योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का दूरदर्शी विचार था। यदि गांवों की खाली पड़ी जमीनों पर जट्रोफा उगाया जाए तो किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है और देश को आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने का अवसर मिल सकता है। कलाम की दृष्टि में यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण विकास—तीनों का संगम था।

उनकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास और वैज्ञानिक तर्क होता था कि लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों ने इस विचार को अभियान के रूप में अपना लिया। लाखों हेक्टेयर भूमि पर जट्रोफा के पौधे लगाए गए। शोध संस्थानों ने इसके बेहतर बीज विकसित करने शुरू किए। किसानों को प्रशिक्षण दिया गया कि वे किस तरह इस फसल से अधिक लाभ कमा सकते हैं। धीरे-धीरे यह आंदोलन भारत की सीमाओं से निकलकर अफ्रीका के देशों तक पहुंचा। वहां के विशेषज्ञों और किसानों ने भी भारतीय अनुभव से सीखकर इस पौधे को अपनाया।

डॉ. कलाम की विशेषता यह थी कि वे किसी भी समस्या को केवल एक कोण से नहीं देखते थे। जट्रोफा उनके लिए सिर्फ ईंधन का स्रोत नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम था। वे चाहते थे कि गांवों के लोग भी आधुनिक विज्ञान से जुड़ें, नई तकनीकों को अपनाएं और आत्मनिर्भर बनें। उनका मानना था कि जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे, तब तक भारत सशक्त नहीं हो सकता।

उनकी सोच में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान था। वे कहते थे कि विकास वही टिकाऊ होता है जो पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर चले। जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ते प्रदूषण को लेकर वे चिंतित रहते थे। इसलिए जैविक ईंधन का उनका विचार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय भी था। कलाम साहब के जीवन से यह सीख मिलती है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे विचारों से शुरू होते हैं। जट्रोफा का सुझाव सुनने में साधारण लग सकता था, लेकिन उसके पीछे छिपी दृष्टि असाधारण थी। वे यह संदेश देना चाहते थे कि समाधान हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस उन्हें देखने वाली आंख चाहिए।

आज जब दुनिया ऊर्जा संकट, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, तब कलाम का यह दृष्टिकोण और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अवसर में बदलना चाहिए। हर नागरिक यदि अपने स्तर पर कुछ नया सोचने और करने का साहस दिखाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है।

डॉ. कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची तरक्की केवल योजनाओं से नहीं, सपनों से जन्म लेती है। उन्होंने करोड़ों युवाओं के मन में यह विश्वास जगाया कि वे भी राष्ट्र निर्माता हैं। जट्रोफा की कहानी दरअसल उसी विश्वास की कहानी है—जहां एक वैज्ञानिक का विचार किसानों के खेतों तक पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया को नई राह दिखाने लगा। भारत की वास्तविक प्रगति उसी दिन होगी जब हम कलाम के इस संदेश को आत्मसात करेंगे कि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपे नवोन्मेष का दीपक जलाए। विकास कोई दूर का लक्ष्य नहीं, रोजमर्रा के छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम है। यदि हम अपनी मिट्टी, अपने संसाधनों और अपनी बुद्धि पर भरोसा करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं। यही डॉ. कलाम का तरक्की का दृष्टिकोण था—आत्मविश्वास से भरा, प्रकृति से जुड़ा और मानवता के लिए समर्पित।

तेल आयात घटा, पर भरोसा और बढ़ा, पुराने दोस्त India-Russia ने आगे बढ़ने के लिए खोज लिये नये रास्ते

भले ही भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन दोनों पुराने दोस्त रिश्तों को जिंदा रखने तथा इसे और मजबूती देने के लिए नये और ज्यादा गहरे रास्ते तलाश रहे हैं। देखा जाये तो ऊर्जा का ग्राफ भले नीचे आया है, पर रणनीतिक साझेदारी की दिशा ऊपर की ओर जाती दिख रही है। हम आपको बता दें कि दिसंबर में भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात में महीने दर महीने करीब 29 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। यह स्तर उस समय के बाद सबसे निचला था, जब रूसी तेल पर मूल्य सीमा नीति लागू हुई थी। यह गिरावट ऐसे समय पर आई जब कुल तेल आयात में मामूली वृद्धि देखी गई। इस गिरावट की मुख्य वजह रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी द्वारा रूसी तेल की खरीद में लगभग 49 प्रतिशत की कटौती और सरकारी रिफाइनरियों द्वारा 15 प्रतिशत की कमी रही। हालांकि यह गिरावट स्थायी नहीं दिखती। जनवरी में रूसी तेल की खरीद फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। जनवरी के 13 दिनों में ही भारत रूस से ग्यारह लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल आयात कर चुका है। वर्ष 2025 में कुल मिलाकर भारत ने रूस से दो करोड़ चार लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मंगाया। मूल्य के लिहाज से देखें तो दिसंबर में भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। भारत ने कुल 23 अरब यूरो के रूसी हाइड्रोकार्बन आयात किये, जिनमें 78 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल का था। कोयला और तेल उत्पाद भी भारत की खरीद का अहम हिस्सा बने रहे। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में यह आंकड़ा इससे अधिक था, लेकिन दिसंबर की गिरावट के बावजूद भारत रूस के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है।

इसी पृष्ठभूमि में भारत और रूस के बीच आर्थिक रिश्तों को ऊर्जा से आगे ले जाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। दिसंबर में हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों ने संयुक्त उद्यमों, स्थानीय उत्पादन और नये व्यापारिक गलियारों पर जोर दिया है। रूस भारतीय कंपनियों के साथ इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल शोधन और धातु उद्योग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को इच्छुक है। रूस का साफ संदेश है कि भारत उसकी विदेशी आर्थिक रणनीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। लक्ष्य यह है कि द्विपक्षीय व्यापार में कच्चे माल और ऊर्जा के अलावा मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़े। भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया और अन्य वैश्विक क्षेत्रों के लिए उत्पादन केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।

इस सहयोग का एक अहम स्तंभ उत्तरी समुद्री मार्ग भी है। यह मार्ग रूस के आर्कटिक क्षेत्र से होकर गुजरता है और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। भारत और रूस इस मार्ग पर स्थिर कार्गो आधार, परिवहन लागत और लॉजिस्टिक्स ढांचे को लेकर साझा मानक तय कर रहे हैं। जहाज निर्माण और परिवहन सेवाओं में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने रूस को अपने निर्यात को दस अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश 2030 तक एक सौ अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत चाहता है कि निर्यात की हिस्सेदारी तीस से पैंतीस अरब डॉलर तक पहुंचे।

देखा जाये तो भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में आई गिरावट को यदि कोई रिश्तों में ठंडापन मान रहा है, तो वह वैश्विक राजनीति की सतह ही देख रहा है, उसकी गहराई नहीं। सच्चाई यह है कि भारत और रूस अब रिश्तों को एक आयामी ऊर्जा निर्भरता से निकालकर बहुस्तरीय रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं। तेल कम हो सकता है, लेकिन भरोसा और आपसी जरूरतें कम नहीं हुई हैं।

हम आपको बता दें कि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में है और उसे ऐसे साझेदार चाहिए जो केवल खरीदार नहीं, बल्कि सह निर्माता और सह निवेशक बनें। भारत इस जरूरत में पूरी तरह फिट बैठता है। वहीं भारत के लिए रूस केवल सस्ता तेल नहीं, बल्कि तकनीक, संसाधन और भू राजनीतिक संतुलन का अहम स्तंभ है। उत्तरी समुद्री मार्ग का उभरना इस साझेदारी को नई ऊंचाई देता है। यह केवल एक शिपिंग रूट नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक व्यापार का वैकल्पिक नक्शा है। जैसे जैसे आर्कटिक क्षेत्र खुल रहा है, वहां शक्ति संतुलन की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत की मौजूदगी उसे दर्शक नहीं, बल्कि सहभागी बनाती है। यह चीन के एकतरफा संपर्क अभियानों के मुकाबले भारत के लिए रणनीतिक संतुलन का साधन भी बन सकता है। देखा जाये तो तेल आयात में उतार चढ़ाव बाजार की जरूरत और मूल्य समीकरण का हिस्सा है, लेकिन संयुक्त उत्पादन, तकनीकी सहयोग और लॉजिस्टिक्स साझेदारी दीर्घकालिक रिश्तों की बुनियाद होती है। रूस का भारत में उत्पादन लगाने का इरादा और भारत की रूस में बाजार विस्तार की चाह इस बात का संकेत है कि दोनों देश भविष्य को लेकर गंभीर हैं। भारत यदि अपने निर्यात को 30 से 35 अरब डॉलर तक ले जाने में सफल होता है, तो यह केवल व्यापारिक उपलब्धि नहीं होगी। यह संकेत होगा कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में केवल ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माता और निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है।

बहरहाल, भारत और रूस का यह नया रास्ता दिखाता है कि वैश्विक दबावों के बीच दोस्ती केवल तेल की पाइपलाइन से नहीं बहती। यह उद्योग, समुद्र, तकनीक और साझा रणनीति के रास्तों से आगे बढ़ती है। और यही इस रिश्ते की असली ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की असली खूबसूरती साफ नजर आती है। वह न तो दबावों में झुकते हैं और न ही रिश्तों को तोड़ने की हड़बड़ी दिखाते हैं।

अभियान

सरयू संवाद: जब नाविक बनेंगे कथावाचक और अयोध्या बनेगी चलती-फिरती पाठशाला

अयोध्या की पहचान केवल मंदिरों, गलियों और घाटों से नहीं बनती, उसकी असली पहचान उन कथाओं से बनती है जो पीढ़ियों से लोगों के हृदय में बहती चली आ रही हैं। सरयू नदी इस नगरी की मौन साक्षी रही है। उसके जल ने राजाओं का वैभव देखा है, संतों की साधना सुनी है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को स्पर्श किया है। अब वही सरयू एक नए सांस्कृतिक अध्याय की गवाह बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से अयोध्या का नौकाविहार केवल सैर-सपाटा नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान, कथा और अनुभव की जीवंत यात्रा बन जाएगा। नाविक अब सिर्फ चप्पू चलाने वाले नहीं, बल्कि रामनगरी के इतिहास और परंपराओं के संवाहक बनेंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने घोषणा की कि अयोध्या में नाविकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे नौकाविहार के दौरान यात्रियों को नगर के प्राचीन स्थलों, मंदिरों, घाटों और लोककथाओं से परिचित करा सकें। अब तक अयोध्या आने वाला यात्री घाटों को देखता था, तस्वीरें खींचता था और लौट जाता था, लेकिन उसे यह कम ही पता चल पाता था कि किस घाट से कौन-सी परंपरा जुड़ी है, किस मंदिर के पीछे कौन-सा प्रसंग छिपा है। इस कमी को दूर करने के लिए यह अनूठी योजना तैयार की गई है, जिसमें स्थानीय नाविकों को कथावाचन, संवाद कला और सांस्कृतिक इतिहास की बारीकियों से जोड़ा जा रहा है।

अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद यह वृद्धि और तेज हुई है। देश के कोने-कोने से लोग यहां आ रहे हैं। सरयू में नौकायन उनके लिए सबसे प्रिय अनुभवों में से एक बन चुका है। शाम के समय जब आरती की ध्वनि गूंजती है और दीपों की माला नदी पर झिलमिलाती है, तब नाव में बैठा हर यात्री एक अलग ही लोक में पहुंच जाता है। सरकार चाहती है कि यही अनुभव और गहरा बने, इसमें ज्ञान और संवेदना का नया रंग घुले। इसलिए 15 से 17 जनवरी तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 55 नाविकों को आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की दक्षताएं सिखाई गईं।

इस प्रशिक्षण का स्वरूप केवल औपचारिक नहीं था। नाविकों को डिजिटल भुगतान की जानकारी दी गई ताकि वे बदलते समय के साथ कदम मिला सकें। आज अधिकतर पर्यटक नकद की बजाय ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान करना पसंद करते हैं। यदि नाविक इस तकनीक से अनभिज्ञ रहेंगे तो उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इसी तरह आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया गया। नदी में नौकायन के दौरान अचानक मौसम बदल सकता है, भीड़ बढ़ सकती है या किसी यात्री की तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित नाविक ही सबसे पहले मददगार बन सकते हैं।

लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था स्टोरीटेलिंग। अयोध्या कथाओं का नगर है। यहां हर पत्थर, हर घाट और हर मंदिर के साथ कोई न कोई प्रसंग जुड़ा है। राम की पैड़ी पर होने वाली आरती, लक्ष्मण घाट का इतिहास, गुप्तार घाट की मान्यताएं, हनुमानगढ़ी की परंपराएं—इन सबकी अपनी-अपनी गाथाएं हैं। अब नाविक इन कथाओं को सरल और रोचक भाषा में यात्रियों तक पहुंचाएंगे। जब नाव सरयू की लहरों पर आगे बढ़ेगी और नाविक की आवाज में रामायण काल के प्रसंग जीवित होंगे, तब पर्यटक केवल दर्शक नहीं, बल्कि उस कथा के सहभागी बन जाएंगे।

सरकार ने इस पहल में मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान और राज्य आपदा मोचन बल को भी जोड़ा है। इसका उद्देश्य पर्यटन को पेशेवर, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। अयोध्या केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अलग-अलग भाषा, प्रांत और देश से होता है। इसलिए नाविकों को व्यवहार कुशलता, संवाद शैली और पर्यटक मनोविज्ञान की भी ट्रेनिंग दी गई। अब वे यात्रियों के प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेंगे, भीड़ को व्यवस्थित कर सकेंगे और अयोध्या की छवि को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे।

इस योजना का सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नाविक समुदाय सदियों से सरयू के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन उन्हें वह सम्मान और अवसर नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे। अब उन्हें औपचारिक पहचान मिलेगी। वे पर्यटन उद्योग की मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे। जब उनकी आय बढ़ेगी, उनका कौशल निखरेगा और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, तब यह पहल सच्चे अर्थों में सफल मानी जाएगी। सरकार चाहती है कि नाविक केवल मजदूर न रहकर सांस्कृतिक दूत बनें, जिनकी आवाज में अयोध्या बोलती हो।

नौकाविहार के इस नए स्वरूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। पर्यटक अधिक समय तक रुकेंगे, स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। छोटे होटल, हस्तशिल्प, प्रसाद सामग्री, गाइड सेवा—सबको इसका लाभ मिलेगा। अयोध्या का विकास केवल भव्य इमारतों से नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी से होगा। यही इस योजना की मूल भावना है।

पर्यावरण संरक्षण को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सरयू अयोध्या की जीवनरेखा है। यदि नदी स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रहेगी तो पूरा पर्यटन प्रभावित होगा। इसलिए नाविकों को प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने, कचरा प्रबंधन और नदी पारिस्थितिकी के बारे में जागरूक किया गया है। यात्रियों को भी स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी अब नाविकों पर होगी। यह पहल आध्यात्मिकता के साथ पर्यावरणीय चेतना का सुंदर संगम है।

धीरे-धीरे यह मॉडल प्रदेश के अन्य नगरों में भी लागू करने की योजना है। काशी में गंगा आरती के समय नाविक यदि घाटों का इतिहास सुनाएं, प्रयागराज में संगम की महिमा समझाएं, मथुरा में यमुना किनारे कृष्ण लीलाओं का वर्णन करें—तो पूरा उत्तर प्रदेश एक चलता-फिरता सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बन सकता है। अयोध्या से शुरू हुई यह यात्रा भविष्य में पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकती है।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल ने पर्यटन को मानवीय स्पर्श दिया है। मशीनों, एप और गाइड बुक से जो अनुभव नहीं मिल सकता, वह एक स्थानीय नाविक की आत्मीय आवाज से मिल सकता है। उसके शब्दों में मिट्टी की खुशबू होती है, परंपरा की सच्चाई होती है। जब वही व्यक्ति यात्रियों को कथा सुनाएगा, तब अयोध्या किताबों की नहीं, जीवन की नगरी लगेगी।

सरयू की लहरें अब केवल नाव को नहीं, कथाओं को भी आगे बढ़ाएंगी। हर नाव एक चलती हुई पाठशाला बनेगी, जहां इतिहास, आस्था और संस्कृति एक साथ सांस लेंगी। यह पहल बताती है कि विकास का अर्थ केवल नई सड़कें या भवन बनाना नहीं, बल्कि लोगों की स्मृतियों और कौशल को सशक्त करना भी है। अयोध्या में शुरू हुआ यह प्रयोग आने वाले समय में पर्यटन की परिभाषा बदल देगा।

जब शाम ढलेगी, दीप जलेंगे और नाव सरयू के बीचो-बीच होगी, तब नाविक की आवाज में गूंजती कथा यात्रियों को एक अलग ही संसार में ले जाएगी। यही वह क्षण होगा जब अयोध्या सचमुच जीवित होगी—अपने लोगों में, अपनी कहानियों में और सरयू की अविरल धारा में।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस संपन्न

मुख्यमंत्री की लोगों की प्रस्तुतियों को सुनकर उनके जिला स्तर पर त्वरित और ईमानदार समाधान के लिए अधिक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने पर ताकीद

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- फील्ड विजिट को प्राथमिकता देकर सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मॉनिटरिंग करें
- ओनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिशन तथा इफेक्टिवनेस के आधार पर समग्र जिले के कामकाज के लिए आह्वान
- सरकार आपके साथ है ; सही व्यक्ति परेशान न हो और गलत व्यक्ति किसी को परेशानी न पहुंचा सके, इसके लिए सूझ-बूझ से बिना किसी डर के अच्छे और नेक कार्यों के लिए कलेक्टर जिला टीम का नेतृत्व करें

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को राज्य के जिला कलेक्टरों को लोगों की प्रस्तुतियां सुनकर उनके त्वरित और प्रामाणिक समाधान के लिए जिला स्तर पर अधिक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करने की ताकीद की है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में प्रस्तुतियां लेकर आने वाले व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे सहायता देने की संवेदनशीलता से ही लोगों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिला स्तर पर ही समाधान संभव हो सके ऐसे प्रश्नों के लिए लोगों को सरकार या विभागों तक न आना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उनका समाधान त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी रूप से हो ।

गांधीनगर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को फील्ड विजिट को प्राथमिकता देकर सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मोनिटरिंग करने के सुझाव दिए। उन्होंने कलेक्टरों से ओनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटिशन तथा इफेक्टिवनेस; इन प्रमुख आधारों पर पूरे जिले के कामकाज का नेतृत्व करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि जिले के प्रमुख के रूप में जो दायित्व उन्हें मिला है, वह जन सामान्य की समस्या के निराकरण की जिम्मेदारी निभाते हुए वहन करने का एक बड़ा अवसर है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि राज्य में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के कारण अब विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं है। ऐसे संजोगों में जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे विकास कार्य तेजी से और गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए जिला टीम का नेतृत्व करते हुए कलेक्टर उचित निगरानी रखें।

श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से टीम वर्क के साथ तथा आपस में चर्चा करते हुए मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि परिपत्रों- नियमों का अलग-अलग अर्थघटन न हो और लोगों को अपने कार्यों में सरलता रहे; इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदारीपूर्वक कार्यरत रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ है और सही व्यक्ति परेशान न हो तथा गलत व्यक्ति किसी को परेशानी न पहुंचा सके; इस उद्देश्य से सूझ-बूझ के साथ बिना किसी डर के अच्छे और नेक कार्यों के लिए जिला टीम का नेतृत्व कलेक्टरों को करना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती स्वस्थ जीवनशैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती का मिशन प्रारंभ किया है। जिला कलेक्टरों से अपने-अपने जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर इस मिशन को सफल बनाने का भी आह्वान किया।

राजस्व राज्य मंत्री श्री संजय सिंह महिडा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित यह कॉन्फ्रेंस राजस्व विभाग के सर्वग्राही कामकाज को और अधिक गति प्रदान करेगा। उन्होंने जिला कलेक्टरों को जनप्रतिनिधियों की प्रस्तुतियों पर उचित कार्रवाई करने, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण में तेजी लाने तथा जिला स्तर पर फीडबैक मैकेनिज्म को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के सुझाव दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन कार्यों के लिए पोर्टल्स का समय-समय पर समीक्षा करने पर भी समर्थन दिया।

इस बैठक में राजस्व राज्य मंत्री ने नई गठित तहसील मुख्यालयों पर लोगों को त्वरित सेवाएं मिलती रहे इसके लिए सरकारी कार्यालयों को शीघ्र कार्यरत करने तथा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आगामी समय में जिला वार समीक्षा बैठकों के आयोजन के सुझाव भी दिए।

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्व सरलीकरण के लोक हितकारी कदम उठाए हैं। इनका लाभ अंतिम स्तर तक पहुंचे; इसके लिए जिला कर्मयोगियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देने का कार्य जिला कलेक्टर अपने हाथ में लें।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तहसील स्तर पर इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के पदों को स्वीकृति दी है, जिससे भूमि से जुड़े मामलों की लंबित संख्या कम होगी। इस दिशा में कलेक्टरों को विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, वरिष्ठ सचिवगण, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, जिला कलेक्टर तथा राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इस एक दिवसीय सम्मेलन में विशेष रूप से आईओआरए/ई-धारा, आईआरसाएमएस, डीसीएलआर/एएलटी के लंबित केसों की समीक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा-मंथन किया गया।

उत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। उत्तर रेलवे अंबाला मंडल के अंतर्गत डाउसनी स्टेशन यार्ड में प्वाइंट नवीनीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—

1.19 जनवरी एवं 24 जनवरी 2026 को हरिद्वार से चलने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन हरिद्वार से 90 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

2.09 फरवरी 2026 को योग नगरी ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन संख्या 22660 योग नगरी ऋषिकेश–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश से 90 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

दक्षिण पूर्व रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। दक्षिण पूर्व रेलवे में ब्लाक के कारण पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—

1.15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी 2026 एवं 05 फरवरी 2026 को अजमेर से चलने वाली ट्रेन संख्या 08612 अजमेर–संतरागाछी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर टोरी–बरकाकाना–मूरी मार्ग से परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी।

2.19 जनवरी, 26 जनवरी 2026 एवं 02 फरवरी 2026 को संतरागाछी से चलने वाली ट्रेन संख्या 08611 संतरागाछी–अजमेर एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर मूरी–बरकाकाना–टोरी मार्ग से परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

पोस्टल शिपमेंट पर निर्यात प्रोत्साहन का 15 जनवरी 2026 से विस्तार - एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा: फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के ड्यूटी ड्रॉबैक, रोडटेप और आरओएससीटीएल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल माध्यम से किए गए निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन का विस्तार करने के फैसले का स्वागत किया है, जो 15 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने इस कदम को प्रगतिशील और लंबे समय से प्रतीक्षित बताया और कहा कि यह छोटे निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को समान अवसर प्रदान करके एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यात को काफी मजबूत करेगा, जो पोस्टल चैनलों पर निर्भर हैं।

उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, लेनदेन लागत कम करेगा और पोस्टल निर्यात को एक मजबूत प्रोत्साहन देगा, जो सीमा पार ई-कॉमर्स का एक उभरता हुआ चालक है। लाभों को लागू करने के लिए, सीबीआईसी ने अधिसूचना संख्या 07/2026–सीमा शुल्क (एनटी) और परिपत्र संख्या 01/2026–सीमा शुल्क के माध्यम से पोस्टल निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 में संशोधन किया है, ये दोनों 15 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे।

श्री रल्हन ने आगे बताया कि ये उपाय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक सुधारों के पूरक हैं, जिसमें विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रावधान, पोस्टल निर्यात का एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण, आईजीएसटी रिफंड का स्वचालन, हब एंड स्पोक मॉडल और देश भर में 1,000 से अधिक डाक निर्यात केंद्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि पोस्टल शिपमेंट पर निर्यात प्रोत्साहन का विस्तार निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक ई-कॉमर्स परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु अंकलेश्वर स्टेशन पर मॉक ड्रिल

(जीएनएस)। वडोदरा रेल मंडल द्वारा आज सूरत - वडोदरा रेल खंड के अंकलेश्वर स्टेशन पर आपदा एवं दुर्घटना प्रबंधन तैयारियों का आकलन करने हेतु एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में कुल 98 रेलवे कर्मचारियों और 25 राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों के सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों की सतर्कता और तैयारियों की जांच करना था। असली इमरजेंसी के दौरान रिस्पॉन्स टाइम कम करने और इंसानी गलतियों को रोकने के लिए समय-समय पर ऐसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मॉक ड्रिल के दौरान प्रातः लगभग 10:43 बजे एक परिकल्पित दुर्घटना के तहत यह स्थिति बनाई गई कि अंकलेश्वर की ICD साइडिंग से मुंबई मंडल स्थित JNPT साइडिंग जा रही एक मालगाड़ी का एक लोडेड वैगन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसके साउथ ट्रॉली के सभी पहिए पटरी से उतर गए तथा कुछ अन्य ट्रैक मैन घायल हो गए। उन्होंने बताया किघटना की जानकारी मिलते ही तत्परता दिखाते हुए वडोदरा से एक्सिडेंट रिलीफ़ मेडिकल इक्विपमेंट (ARME) तथा एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) एवं उधना से एक्सिडेंट रिलीफ़ ट्रेन (ART) तुरंत अंकलेश्वर भेजी गई। साथ ही वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके अन्य वरिष्ठ अधिकारिओं के साथ तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुए।

अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की आपातकालीन तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय तथा राहत कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। ड्रिल के दौरान प्राथमिक उपचार, भीड़ नियंत्रण, संचार व्यवस्था, संरक्षा उपाय तथा राहत गतिविधियों का विस्तृत अनुकरण किया गया।

नवसारी मनपा के बाहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाले जलापूर्ति एवं ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार शहरीकरण को गति देने के साथ-साथ नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार शहरों के विस्तार के साथ ही नए शामिल होने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति, ड्रेनेज पाइपलाइन, सड़क एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसके अंतर्गत हाल ही में नवसारी महानगर पालिका ने 112 करोड़ रुपए की जलापूर्ति और ड्रेनेज परियोजना कार्यान्वित की है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2025 को नवसारी महानगर पालिका का गठन किया गया था, जिसमें पहले के नवसारी विजलपोर नगर पालिका क्षेत्र के साथ 4 निकटवर्ती गांवों एरु, धारागीरी, दांतेज और हांसापोर को शामिल किया गया। शहर के इन बाहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल और ड्रेनेज की लाइनों के अभाव के कारण पीने के पानी और ड्रेनेज की गंभीर समस्या थी। इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए नवसारी महानगर पालिका द्वारा इन क्षेत्रों में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से एक नया जलापूर्ति और ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जा रहा है।

- नवसारी में नए ड्रेनेज और जलापूर्ति नेटवर्क से पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मिलेगी राहत
- गुजरात सरकार का जल प्रबंधन के कार्यों से छोटे शहरों को समस्याओं से मुक्त करने का अर्बन विजन

112 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले नए ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

इस परियोजना के अंतर्गत महानगर पालिका द्वारा चरणबद्ध तरीके से नई पानी और ड्रेनेज की पाइपलाइनें, ओवरहेड टंकी और भूमिगत सम्प, ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे 25,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को पेयजल और गंदे पानी की निकासी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर, बच्चों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी अंत आएगा। नवसारी में जलापूर्ति और नया ड्रेनेज नेटवर्क केवल ढांचागत सुविधाओं में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि यह शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। नवसारी मनपा क्षेत्र में शामिल किए गए चार गांवों में सड़क, लाइट, ड्रेनेज और पानी के नए नेटवर्क के अलावा उद्यान और तालाबों का विकास कर विहार धाम का निर्माण, सिविक सेंटर और सफाई के लिए डस्टबिन वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है। नवसारी महानगर पालिका के आयुक्त श्री देव चौधरी ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि "नए साल में नवसारी महानगर पालिका शहर में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। जिसमें ड्रेनेज, सड़कें, स्टॉर्म वाटर और पानी की व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसी उद्देश्य से शहर में शामिल किए गए चार गांवों में ड्रेनेज, पानी और स्टॉर्म वाटर का समग्र नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में इन चार गांवों में ड्रेनेज और जलापूर्ति का काम किया जाएगा। यह परियोजना निर्धारित समयरेखा के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है, जिससे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी और उनकी सुख-सुविधा में वृद्धि होगी।"

गुजरात की विकास यात्रा में मील का पत्थर बना 'शहरी विकास वर्ष'

वर्ष 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' मनाने की शुरुआत की थी और शहरी विकास के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की थीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस विकास यात्रा को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि उन्होंने 20 वर्ष बाद, 2025 को एक बार फिर 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

पश्चिम रेलवे द्वारा 26 जनवरी, 2026 से मुंबई उपनगरीय खंड में और 12 एसी लोकल ट्रेनों की शुरुआत,एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121

(जीएनएस)। यात्रियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा सोमवार, 26 जनवरी, 2026 से मुंबई उपनगरीय खंड में एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 12 नई एसी लोकल सेवाओं की शुरुआत के साथ एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या अब 109 से बढ़कर 121 हो जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एसी लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः यात्रियों की सुविधा के लिए तथा भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे पर मौजूदा नॉन-एसी 12 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों के स्थान पर 12 अतिरिक्त एसी लोकल सेवाएँ शुरू की जा रही हैं। ये सभी सेवाएँ सप्ताह के सभी दिनों में एसी सेवाओं के रूप में परिचालित होंगी। लोकल ट्रेनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात कुल 1406 लोकल सेवाएँ यथावत रहेंगी, जिनमें से 121 सेवाएँ एसी लोकल ट्रेन सेवाएँ होंगी। श्री विनीत ने आगे बताया कि शुरू की जा रही 12 और एसी लोकल ट्रेनों में से 6 ट्रेनें अप दिशा में और 6 ट्रेनें डाउन दिशा में हैं। अप दिशा में, विरार – चर्चगेट और गोरेगांव – चर्चगेट के बीच 2-2 ट्रेनें तथा बोरीवली – चर्चगेट और भायंदर – चर्चगेट के बीच एक-एक ट्रेन है। इसी तरह, डाउन दिशा में, चर्चगेट – विरार और चर्चगेट – गोरेगांव के बीच 2-2 ट्रेनें तथा चर्चगेट – भायंदर और चर्चगेट – बोरीवली के बीच एक-एक ट्रेन है।

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में ब्लॉक के कारण ट्रेनें प्रभावित

(जीएनएस)। रतलाम, 16 जनवरी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के गोरखपुर–गोंडा रेलखंड में तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रभावित

ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेनें –

गाड़ी संख्या 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल जो पूर्व में 13 फरवरी 2026 तक निरस्त थी, उसे अब बढ़ाकर 27 मार्च 2026 तक निरस्त किया गया है।

गाड़ी संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल जो पूर्व में 14 फरवरी 2026 तक निरस्त थी, उसे अब बढ़ाकर 28 मार्च 2026 तक निरस्त किया गया है।

शॉर्ट टर्मिनेशन /आंशिक रूप से निरस्तीकरण :-

गाड़ी संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जो पूर्व में 08 फरवरी 2026 तक बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जा रही थी, 29 मार्च 2026 तक बलरामपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

गाड़ी संख्या 22922 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस जो पूर्व में 10 फरवरी 2026 तक बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ऑरिजिनेट की जा रही थी, 31 मार्च 2026 तक बलरामपुर स्टेशन से शॉर्ट ऑरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन संचालन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट, रेल मदद ऐप अथवा 139 रेल मदद नंबर का उपयोग करें।

जनसंपर्क विभाग
रतलाम मंडल

ममता बनर्जी का दो टूक संदेश: धमकियों से नहीं डरूंगी, बलिदान के लिए तैयार

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर कड़ा हमला करते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें किसी भी तरह की धमकी या दबाव से पीछे नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह आम जनता के हित में अपनी जान तक देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने यह बयान उत्तर बंगाल के दो दिवसीय दौरे के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया।

ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एजेंसियों के काम में बाधा डाली है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह किसी भी तरह से उन्हें कमजोर नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनका संकल्प जनता के अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए अडिग है।

राज्य में व्याप्त तनाव और हिंसक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में प्रवासी मजदूर की मौत के विरोध में हुए सड़क और रेल अवरोध का जिक्र किया और पूर्व बर्दवान के समुद्रगढ़ स्टेशन पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही। ममता का आरोप है कि इन घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश है और राज्य में अशांति फैलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वास्तविक कारण हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा और तोड़फोड़ पूरी तरह गलत है। उन्होंने लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है।

ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, मतुआ और राजबंशी समुदायों के नाम साजिशन हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल पश्चिम बंगाल में ही इस प्रक्रिया के जरिए असामान्य दबाव बनाया जा रहा है, जिससे भ्रम और असंतोष फैलाया जा रहा है।

आई-पैक कार्यालय में हुई तलाशी के मामले पर ममता ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और कुछ लोग जानबूझकर यह प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि वह न तो डरेंगी और न ही जनता के अधिकारों की लड़ाई से पीछे हटेंगी।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि उनके संकल्प और जनहित के लिए उनका समर्पण अडिग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की धमकी, जेल भेजने की अफवाह या डराने की कोशिश उन्हें रोक नहीं सकती। ममता ने दोहराया कि उनकी प्राथमिकता हमेशा राज्य के नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना रही है और इसके लिए वह हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। राज्य में जारी राजनीतिक और सामाजिक तनाव को लेकर ममता ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और एजेंसियों पर यह भी आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य केवल बंगाल में अशांति फैलाना और विपक्षी नेताओं को डराना है। उन्होंने कहा कि वह न केवल व्यक्तिगत रूप से इस तरह की धमकियों के खिलाफ अडिग हैं, बल्कि जनता के हित में लड़ाई जारी रखेंगी।

ममता बनर्जी का यह बयान राज्य में राजनीतिक माहौल को और गरमाएगा, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा कि वह अपने मतदाताओं के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान को तैयार हैं। उनके इस संदेश से यह स्पष्ट है कि आगामी दिनों में वे जनता के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगी।

मुख्यमंत्री ने अपनी बात में जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल सतर्क हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भी शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।

इस प्रकार, ममता बनर्जी ने केंद्र और एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया कि धमकियों और डराने की कोशिशों से वह नहीं डरेंगी और जनता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यह बयान राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी घटनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में 107 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता का वितरण किया

▸▸ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना तथा जेटको और पीजीवीसीएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत एलिम्को निःशुल्क दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण कैंप आयोजित

▸▸ राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर 820 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं : केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया

▸▸ श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने की संवेदनशील पहल की : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा काम किया

▸▸ दिव्यांगजनों के लिए वरदान बने दिव्याशा केंद्र

▸▸ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए गांधीनगर में 316 करोड़ रुपए के खर्च से एथलीट्स हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हो रहा है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय खेलों में अधिक मेडल जीत सकें

▸▸ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'सशक्त दिव्यांगजन यानी सशक्त भारत' विजन के साथ गत 10 वर्षों में दिव्यांग कल्याण योजनाओं के खर्च में तीन गुना वृद्धि हुई

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को भावनगर में दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण शिविर के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने दिव्यांगों का जीवन आसान और उन्नत बनाने के लिए दिव्यांगजनों के हित में अनेक निर्णय किए हैं। भावनगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता योजना (एडिप योजना) और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेटको) और पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत एलिम्को और भावनगर जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क दिव्यांग साधन-उपकरण सहायता वितरण कैंप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक ही दिन में एक साथ 1017 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता वितरित करने के इस कार्यक्रम को दिव्यांग कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया। मुख्यमंत्री ने भावनगर और बोटाद जिले में 15 दिनों तक कैंप आयोजित कर 2600 से अधिक दिव्यांगजनों को 3.51 करोड़ रुपए के 4800 से अधिक साधनों का निःशुल्क वितरण कर उनकी आत्मनिर्भरता का अहम कार्य करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया और उनकी टीम को बधाई दी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के दो सार्वजनिक उपक्रमों जेटको और पीजीवीसीएल की भी सीएसआर के तहत इस साधन वितरण में योगदान देने के लिए सराहना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में पिछले पांच वर्ष में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर 820 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। इतना ही नहीं, दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के लिए बार-बार मेडिकल चेकअप कराने की मुश्किलों से भी मुक्ति मिली है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने के निर्णय से दिव्यांगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब 60 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधितों को संत सूरदास योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने के कारण दिव्यांगजन आत्मसम्मान से जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में दिव्यांगों का जीवन बदला और उन्हें नए अवसर प्रदान किए हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा कार्य किया है। इस अभियान के कारण देश में सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित की गई हैं और ईज ऑफ लिविंग से उनका जीवन आसान बना है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की 'प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र' के निर्माण की पहल की चर्चा करते हुए कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 300 दिव्याशा केंद्र बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 100 तो कार्यरत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए भी श्री मोदी ने योजनाबद्ध कार्यपद्धति अपनाई है। इस बारे में उन्होंने कहा कि गांधीनगर में 316 कोरड़ रुपए की लागत से पैरा एथलीटों के लिए हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस सेंटर में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे आने वाले समय में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल जीत सकें। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में दिव्यांगजनों के शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और उद्योगों में समान भागीदार बनाने की मंशा व्यक्त की।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। बोटाद और भावनगर जिले में लगभग 2700 दिव्यांगजनों का परीक्षण किया गया था। भावनगर जिले में शिहोर और पालीताणा तथा बोटाद जिले में तीन कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिनमें 825 दिव्यांगजनों को कुल 121.20 लाख रुपए मूल्य के 1577 साधन वितरित किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एडिप योजना के तहत लाखों दिव्यांगजनों को निःशुल्क आधुनिक सहायक साधन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत 11 वर्षों में दिव्यांगजनों को साधन-सहायता के लिए लगभग 18 हजार से अधिक कैंपों का आयोजन कर 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों तक सहायता पहुंचाई गई है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि 'दिव्यांग' शब्द की भावनात्मक अभिव्यक्ति और दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्थाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिव्यांगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जो संवेदनशील पहले की थी, उसका फल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिव्यांग साधन सहायता कार्यक्रमों के जरिए अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी विनम्रता, निष्कपटता और संवेदनशील कार्य शैली के माध्यम से गुजरात में एक मजबूत नेतृत्व स्थापित किया है। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायी बना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों की प्रशंसा की।

श्री वाघाणी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां सीएसआर फंड का उचित उपयोग समाज के हित में करने के लिए आगे आ रही हैं। दिव्यांगजनों को साधन सहायता मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शुभकामना संदेश पढ़ा गया।

भावनगर कलेक्टर डॉ. मनीष कुमार बंसल ने स्वागत भाषण दिया जबकि जिला विकास अधिकारी श्री हनुल चौधरी ने आभार व्यक्त किया। एलिम्को कंपनी के महाप्रबंधक श्री विवेक द्विवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा देते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर भावनगर के प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, महापौर श्री भरतभाई बारड़, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजूभाई राबड़िया, उप महापौर श्रीमती मोनाबेन पारेख, विधायक सर्वश्री सेजलबेन पंड्या, भीखाभाई बारैया, शंभुनाथ टुंडिया, गौतमभाई चौहाण, शिवाभाई गोहिल, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री रवि शंकर, अग्रणी श्री कुमारभाई शाह और दिग्विजयसिंह गोहिल सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

अहमदाबाद मण्डल पर मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में दिनांक 16.01.2026 को मण्डल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की चतुर्थ बैठक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में आयोजित की गई। बैठक के प्रारम्भ में मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए उनके-अपने क्षेत्रों से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए। समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अहमदाबाद मण्डल में चल रही विभिन्न गतिविधियों एवं विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं में निरंतर सुधार करना तथा यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाना मण्डल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी समय में मण्डल के विभिन्न स्टेशनों पर और अधिक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री त्यागी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मण्डल की प्रमुख उपलब्धियों एवं विकास कार्यों की जानकारी

दी। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, साबरमती एवं भुज स्टेशनों का मेजर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर है, जिनमें साबरमती एवं भुज स्टेशनों का कार्य उन्नत चरण (advance stage) में है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास "अमृत स्टेशन योजना" के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि गेज परिवर्तन एवं अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों में तेजी लाई गई है। हाल ही में आंबलियासन–विजापुर तथा मोटी–विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है और इस खंड का सीआरएस निरीक्षण भी सम्पन्न हो गया है। शीघ्र ही इस सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित रेल समस्याओं, ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, ट्रेनों का स्टोपेज प्रदान करने, नई ट्रेन सेवा शुरू करने एवं अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज बनाने तथा नई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मण्डल रेल प्रबंधक ने प्रस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर समिति के सदस्य सर्वश्री राकेश कुमार जैन,हिंगोरभाई रबारी, जामाभाई देसाई, भगवानभाई एच.पटेल, भगवानदास के.पटेल, जितेन्द्र कुमार लेउवा, संजयभाई पटेल, दिलीपभाई पंड्या, किशोर ठाकुर, क्षितीश शाह, मुकेशकुमार ठाकर, अरविन्दभाई नायक, अनिकुमार पटेल, आर पी शर्मा, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मण्डल रेल प्रबंधक विकास गढ़वाल एवं मण्डल के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे तथा बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

न्यूमी का पहला प्रीमियम स्टोर जयपुर में लॉन्च शाही विरासत और आधुनिक फैशन का संगम

(जीएनएस)। जयपुर। महिलाओं के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे ओमनीचैनल फैशन-टेक ब्रांड न्यूमी ने शुक्रवार को जयपुर में अपना पहला प्रीमियम स्टोर खोला। गुलाबी नगरी के वैशाली सर्कल, ब्लॉक सी में स्थापित यह स्टोर 3,000 वर्गफीट में फैला हुआ है और दो मंज़िला आधुनिक रीटेल फॉर्मेट के साथ ग्राहकों को विशेष अनुभव प्रदान करता है। स्टोर का डिज़ाइन जयपुर की शाही विरासत से प्रेरित है और इसमें रानियों की झलक के साथ न्यूमी के आधुनिक एवं ट्रेंडी डिज़ाइनों का अनूठा संयोजन देखने को मिलता है। ग्राहक इस स्टोर में फैशन और प्रौद्योगिकी के अद्वितीय मिश्रण का अनुभव कर सकते हैं। स्टोर में विशेष इंस्टाग्राम कॉर्नर की व्यवस्था की गई है, जहां ग्राहक स्टाइलिश पलों को कैद कर सकते हैं। यह सुविधा ब्रांड के आधुनिक फैशन अनुभव को और अधिक जीवंत बनाती है और सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए आकर्षक बनाती है।

न्यूमी के सह-संस्थापक और सीईओ सुमित जसोरिया ने बताया कि इस स्टोर की शुरुआत का उद्देश्य राजस्थान में ब्रांड की उपस्थिति मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि अगले कुछ महीनों में ब्रांड जोधपुर और उदयपुर में भी स्टोर खोलकर राज्य में विस्तार करेगा। उनका कहना है कि न्यूमी का ओमनीचैनल दृष्टिकोण ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक समान अनुभव प्रदान करता है।

ब्रांड ने 2022 से अब तक 17 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा दी है और हर सप्ताह लगभग 1,000 नए डिज़ाइन पेश करता है। यह तेज़ आपूर्ति श्रृंखला और इन्वेंटरी-लाईट मॉडल सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को हमेशा नवीनतम और आकर्षक फैशन विकल्प उपलब्ध हों। जसोरिया ने कहा कि न्यूमी का उद्देश्य केवल कपड़े बेचना नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए एक जीवनशैली ब्रांड बनना है, जो उनके व्यक्तित्व और फैशन समझ को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। स्टोर के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित ग्राहकों और फैशन इन्फ्लुएंसर्स ने इस नए ब्रांड एक्सपीरियंस की तारीफ की। स्टोर का वातावरण आकर्षक रंगों, रोशनियों और आधुनिक सजावट के माध्यम से ग्राहकों को एक प्रीमियम शॉपिंग अनुभव प्रदान करता है। जयपुर में न्यूमी के इस स्टोर की शुरुआत से स्थानीय फैशन बाजार में एक नया उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि यह स्टोर युवाओं और फैशन प्रेमियों के लिए केंद्र बिंदु बन जाएगा। जसोरिया ने यह भी बताया कि ब्रांड के विस्तार की रणनीति में राजस्थान के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में भी स्टोर खोलने की योजना शामिल है। उनका मानना है कि आधुनिक महिला उपभोक्ता अब केवल स्टाइल और डिज़ाइन की तलाश में नहीं हैं, बल्कि उन्हें ब्रांड के साथ जुड़ाव और अनुभव की भी आवश्यकता है। न्यूमी का यह स्टोर इसे ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, ताकि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान एक अनूठा और व्यक्तिगत अनुभव मिले।

स्टोर में उपलब्ध कलेक्शन में परंपरागत और आधुनिक डिज़ाइन का संगम देखने को मिलता है, जो स्थानीय संस्कृति के साथ वैश्विक फैशन ट्रेंड को जोड़ता है। ग्राहकों को कपड़े, एक्सेसरीज़ और आधुनिक ट्रेंडी उत्पादों के साथ-साथ व्यक्तिगत स्टाइलिंग के विकल्प भी मिलते हैं। न्यूमी का यह प्रीमियम स्टोर फैशन तकनीक और परंपरा के संगम का प्रतीक है, जो जयपुर की शाही विरासत के अनुरूप एक आधुनिक शॉपिंग अनुभव प्रदान करता है।

जयपुर स्टोर के माध्यम से न्यूमी ने यह संदेश दिया है कि ब्रांड न केवल भारतीय महिलाओं के फैशन विकल्प बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर की शैली और नवीनतम डिज़ाइन भी उपलब्ध करा रहा है। यह स्टोर फैशन टेक्नोलॉजी को स्थानीय संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़कर एक नया मानक स्थापित करता है।

ग्राहक प्रतिक्रिया के अनुसार, न्यूमी का यह स्टोर खरीदारी के अनुभव को केवल उत्पाद तक सीमित नहीं रखता, बल्कि यह एक जीवनशैली और ब्रांड अनुभव का हिस्सा बनता है। इंस्टाग्राम कॉर्नर और स्टाइलिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को ब्रांड के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है।

इस लॉन्च से जयपुर में स्थानीय फैशन बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह स्टोर ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता और प्रीमियम डिज़ाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। न्यूमी का यह प्रयास दर्शाता है कि फैशन ब्रांड्स अब केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्राहकों के अनुभव और जीवनशैली को भी समृद्ध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

न्यूमी के इस स्टोर के उद्घाटन से शहर में फैशन प्रेमियों के लिए नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। जयपुर के ग्राहकों के लिए यह स्टोर न केवल खरीदारी का स्थल बनेगा, बल्कि यह फैशन, स्टाइल और आधुनिक जीवनशैली का प्रतीक भी होगा।

क्रूड ऑयल वायदा 83 रुपये तेज: सोना वायदा में 31 रुपये और चांदी वायदा में 104 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149028.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 40110.56 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 108912.9 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 38970 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2688.48 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 33023.16 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 142589 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 143296 रुपये और नीचे में 142400 रुपये पर पहुंचकर, 143121 रुपये के पिछले बंद के सामने 31 रुपये या 0.02 फीसदी की तेजी के संग 143152 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 248 रुपये या 0.21 फीसदी औंधकर 116000 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 10 रुपये या 0.07 फीसदी औंधकर 14532 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 142415 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142950 रुपये और नीचे में 142002 रुपये पर पहुंचकर, 6 रुपये या 0 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 142856 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 143131 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 143595 रुपये और नीचे में 142700 रुपये पर पहुंचकर, 143406 रुपये के पिछले बंद के सामने 14 रुपये या 0.01 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 143420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 287127 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 292865 रुपये और नीचे में 285513 रुपये पर पहुंचकर, 291577 रुपये के पिछले बंद के सामने 104 रुपये या 0.04 फीसदी बढ़कर 291681 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 471 रुपये या 0.16 फीसदी की मजबूती के साथ 293892 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 341 रुपये या 0.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 293881 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 40110.56 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 108912.9 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 33023.16 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38970 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3391.98 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 10.6 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 1297.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता जनवरी वायदा रु.1.3 या 0.41 फीसदी औंधकर 316.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी औंधकर 316.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 191.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3470.22 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5340 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5438 रुपये और नीचे में 5314 रुपये पर पहुंचकर, 83 रुपये या 1.55 फीसदी बढ़कर 5430 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 86 रुपये या 1.61 फीसदी की तेजी के संग 5430 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 285.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 292 रुपये के दिन के उच्च और 283.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 283.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.4 रुपये या 1.91 फीसदी की बढ़त के साथ 288.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5.5 रुपये या 1.94 फीसदी की बढ़त के साथ 288.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 970 रुपये के भाव पर खूलकर, 2.2 रुपये या 0.23 फीसदी की मजबूती के साथ 976.5 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11675.90 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21347.26 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2843.61 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 290.18 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 23.71 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 753.97 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2697.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20822 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 79399 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26839 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 400953 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 45330 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13916 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38721 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 98732 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22393 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 48959 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 38201 पॉइंट पर खूलकर, 39030 के उच्च और 37820 के नीचले स्तर को छूकर, 56 पॉइंट बढ़कर 38970 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 36.9 रुपये की बढ़त के साथ 267.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.4 रुपये की बढ़त के साथ 12.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 147000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 241 रुपये की गिरावट के साथ 639 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 295000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1682.5 रुपये की गिरावट के साथ 13189 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 7.79 रुपये की गिरावट के साथ 25.72 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.2 रुपये की गिरावट के साथ 3.3 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 55.6 रुपये की गिरावट के साथ 213.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.85 रुपये की गिरावट के साथ 12.85 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 107.5 रुपये की गिरावट के साथ 786 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 285000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 855.5 रुपये की गिरावट के साथ 11816.5 रुपये हुआ।

तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.52 रुपये की बढ़त के साथ 29.06 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।